# HRA an USIUSI The Gazette of India

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2012/आश्विन 30, 1934

No. 540]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2012/ASVINA 30, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 781(अ),—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शिकां में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 33 द्वारा प्रदत्त शिकां का प्रयोग करते हुए और तारीख 6 अगस्त, 2012 को बंगलौर, कर्नाटक में मामले की शमनीयता की असलीयत को देखते हुए, एतद्द्वारा, मैसर्स कोकुयो कैमिलन लि., 48/2, हिल्टन हाऊस, सेन्ट्रल रोड, एम.आई.डी.सी., अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400093 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अथवा पैकिंग सामग्री या रैपर के समाप्त हो जाने की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, इन नियमों के अधीन अपेक्षित सुधार करने के पश्चात्, अर्थात् यथास्थिति मुहर अथवा स्टिकर लगाकर या आन लाइन छपाई करके, कम्पनी का नया नाम देते हुए, कम्पनी के पुराने नाम सिहत पुरानी पैकिंग सामग्री का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करती है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम.-10(28)/2012] मनोज कुमार परिडा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2012

GS.R. 781(E).—In exercise of the powers conferred by rule 33 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, and in view of the genuineness of the compounding of the case at Bangalore, Karnataka on the 6th August, 2012, the Central Government hereby permits M/s. Kokuyo Camlin Limited, 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093 to use the old packaging material with the old name of the company for a period of six months from the date of publication of this notification in the official gazette or till such date the packaging material or wrapper is exhausted, whichever is earlier, after making the corrections required under these rules, namely, giving the new name of the company by way of stamping or putting sticker or online printing, as the case may be.

[F. No.WM-10(28)/2012]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.